



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 18, 2013/आश्विन 26, 1935

No. 236]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2013/ASVINA 26, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2013

विषय : चीन जन.गण. के मूल के या वहां से निर्यातित इलैक्ट्रानिक कैलकुलेटरों के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

सं. 14/19/2013-डीजीएडी : यतः चीन जन.गण., (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित इलैक्ट्रानिक कैलकुलेटरों (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए अर्जंता लि० (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) ने घरेलू उद्योग की ओर से समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है), के अनुसार, संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों की पाटनरोधी जांच शुरु करने और उन पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है ।

2. और यतः प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथमदृष्टया साक्ष्य को मौजूद पाते हैं; तथा प्राधिकारी किसी आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लागू किया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार, आरोपित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति के बारे में एतद्वारा जांच शुरु करते हैं ।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद इलैक्ट्रानिक कैलकुलेटर हैं। इलैक्ट्रानिक कैलकुलेटर एक लघु तथा वहनीय इलैक्ट्रानिक यंत्र होता है जिसका उपयोग अंकगणितीय संकार्यों और कुछ अन्य गणितीय कार्यों में किया जाता है। संख्या संबंधी साधारण संकार्यों में शामिल हैं: जोड़, भिन्न, गुणा तथा भाग। जटिल गणितीय संकार्यों में शामिल हैं, घातांकी संकार्य, मूलक, लघुगणक, त्रिकोणमितीय संकार्य, और अति परवलयिक फलन आदि तथा इनमें इसके सभी वाणिज्यिक/व्यापारिक भाषा के नाम शामिल हैं।

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'सभी प्रकार के इलैक्ट्रानिक कैलकुलेटर' हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

क. ऐसे कैलकुलेटर, जिनके साथ प्रिंटर लगे हुए हैं जिन्हें आमतौर पर प्रिंटिंग कैलकुलेटर कहा जाता है।

ख. चार्ट एवं ग्राफ बनाने की क्षमता वाले कैलकुलेटर जिन्हें आमतौर पर ग्राफिंग कैलकुलेटर कहा जाता है।

ग. प्रोग्राम साध्य कैलकुलेटर

घरेलू उद्योग का आधार

5. यह आवेदन भारत में विचाराधीन उत्पाद के एकमात्र उत्पादक मै0 अजंता लि0 ने दायर किया है। उपलब्ध सूचना से प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु का उत्पादन भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 'एक बड़ा भाग' बनता है। अतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंड को पूरा करता है।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से भारत में आयातित वस्तु, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, वितरण एवं विपणन, कीमत तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी तकनीकी विशेषताओं के रूप में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इस प्रकार इन्हें नियमानुसार "समान वस्तु" माना जाए। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु को "समान वस्तु" माना जा रहा है।

संबद्ध देश

7. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन.जन.गण. है।

सामान्य मूल्य

8. आवेदक ने दावा किया है कि चीन.जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। आवेदक ने सामान्य मूल्य का दावा विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया है। नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन.जन.गण. में सम्बद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं। उपर्युक्त बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान के मद्देनजर और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन रहते हुए चीन.जन.गण. में सम्बद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार लगाया गया है।

निर्यात कीमत

9. आवेदक द्वारा निर्यात कीमत का दावा इन्फ्रोडाइव (इंडिया) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इसी स्रोत के आंकड़ों पर जांच अवधि सहित क्षति अवधि के लिए विचार किया गया है। निवल कारखाना निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय भाड़े तथा बैंक प्रभारों के लिए प्रथम दृष्टया कीमत समायोजन की अनुमति दी गई है।

पाटन मार्जिन

10. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार पर की गई है जिससे सम्बद्ध देश के बारे में अत्यधिक पाटन मार्जिन का पता चलता है। इस बात का पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य भारत के लिए कारखाना निर्यात कीमत से अधिक है जिससे प्रथमदृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है। अनुमानित पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

11. आवेदक ने पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि, कीमत कटौती, कीमत हास, नकारात्मक लाभप्रदता, वित्तीय घाटे, लगाई गई पूंजी पर आय में गिरावट तथा नकद प्रवाह में गिरावट आदि के रूप में आरोपित पाटन के परिणामस्वरूप हो रही 'क्षति' के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया है। पाटनरोधी जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही "क्षति" का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है।

जांच अवधि

12. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक की मानी है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2009 – मार्च 2010, अप्रैल, 2010 – मार्च, 2011, अप्रैल, 2011 – मार्च, 2012 की अवधि और जांच अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के जरिए उसकी सरकार, विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर इस जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है और निम्नलिखित पते पर लिख सकता है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग,

भारत सरकार

कमरा सं. 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

समय-सीमा

14. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 (चालीस) दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में पहुंच जानी चाहिए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उनसे उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की

तारीख से 40 (चालीस) दिनों के भीतर सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं। यह नोट किया जाए कि निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने के बारे में किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

15. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सैटों (क) गोपनीय रूप में अंकित (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।
16. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। गोपनीय रूपांतरण और अगोपनीय रूपांतरण प्रत्येक की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।
17. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु, सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है।
18. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।
19. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
20. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

21. नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

22. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 18th October, 2013

Subject : Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Electronic Calculators originating in or exported from China PR.

F. No.14/19/2013-DGAD.—Whereas Ajanta Ltd. (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Rules), alleging dumping of Electronic Calculators (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country), for initiation of anti-dumping investigation and for levy of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

2. And Whereas, the Authority finds sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from subject country, and injury to the domestic industry, and causal link between the dumping and injury and hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the Anti-dumping Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping

and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present investigation is Electronic Calculators. An electronic calculator is a small and portable electronic device used for performing arithmetic operations and certain other mathematical functions. Simple numeric operations include basic arithmetic such as addition, subtraction, multiplication and division. Complex mathematical functions include exponential operations, roots, logarithms, trigonometric functions, and hyperbolic functions, etc. and include all its commercial/trade parlance names.

4. The product under consideration for the present investigation is 'Electronic Calculator of all types', excluding the following:

- a. Calculators with attached printers, commonly referred to as *printing calculators*
- b. Calculators with ability to plot charts and graphs, commonly referred to as *graphing calculators*
- c. *Programmable calculators*

DOMESTIC INDUSTRY STANDING

5. The application has been filed by M/s Ajanta Ltd., the sole producer of the product under consideration in India. From the available information, the Authority prima facie notes that the production of subject goods produced by the domestic producer accounts for "a major proportion" of total production of the product under consideration in India. The Authority, therefore, prima facie determines that the applicant constitutes domestic industry within the meaning of the Rule 2 (b) of Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules *supra*.

LIKE ARTICLE

6. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are like articles to the goods produced by the domestic industry. There are no differences between the goods produced by the applicant and goods imported into India from the subject country in terms of technical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing, pricing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and hence be treated as 'like article' under the Rules. For the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated prima facie as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

COUNTRY INVOLVED

7. The country involved in the present investigation is China PR.

NORMAL VALUE

8. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and determined normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

EXPORT PRICE

9. The applicant has claimed export prices on the basis of data obtained from Infodrive (India). The data from the same source has been taken into consideration for the injury period including the POI. Price adjustments have been prima facie allowed on account of overseas freight, overseas insurance, commission, port expenses, and inland freight and bank charges to arrive at the net ex-factory export price.

DUMPING MARGIN

10. Normal value and export price have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of each of the subject country. There is prima facie evidence to show that the normal value of the subject goods in each of the subject country is significantly higher than the ex-factory export price to India, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margins estimated are significantly above de minimis.

INJURY AND CAUSAL LINK

11. The applicant has furnished evidence regarding the 'injury' having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price depression, negative profitability, financial losses, declining return on capital employed, declining cash flow, etc. There is sufficient prima

facie evidence of 'injury' being suffered by the domestic industry, caused by dumped imports from the subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

PERIOD OF INVESTIGATION

12. The Authority has considered the period of investigation for the purpose of the present investigation from 1st April 2012 to 31st March 2013. The injury investigation period will however cover the periods April 2009-March 2010, April 2010- March 2011, April 2011-March 2012 and the POI.

SUBMISSION OF INFORMATION

13. The known exporters in the subject country and the Government through its respective Embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the product under consideration and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Government of India,
Room No. 240,
Udyog Bhavan, New Delhi -110011.

TIME LIMIT

14. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than 40 (forty) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers who are being addressed separately are, however, required to submit the information within 40 (forty) days from the date of the letter addressed to them separately. If no information is received within the prescribed time limit or the submitted information is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules. It may be noted that no request, whatsoever, shall be entertained for extension in the prescribed time limit.

SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

15. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non- Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

16. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

17. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such confidential information.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

21. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by the interested parties.

NON-COOPERATION

22. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority